ईरान से तेल की खरीद बंद करने के लिए भारत पर अमेरिकी दबाव बढ़ता जा रहा है. पिछले साल नवंबर में ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लागू करते समय अमेरिका ने भारत समेत कुछ देशों को छह माह की छूट दी थी, जिसकी अवधि मई में पूरी हो रही है. यदि भारत इस पाबंदी के अनुसार ईरान से तेल नहीं लेता है, तो उसे दूसरे देशों से आयात बढ़ाना होगा. हालांकि, अमेरिका ने भरोसा दिलाया है कि चाबहार बंदरगाह परियोजना पर प्रतिबंध का असर नहीं होगा, पर निश्चित रूप से ईरान के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध पहले की तरह नहीं रह जायेंगे. एक प्रश्न यह भी है कि अमेरिकी प्रतिबंध पर सहयोग करने से भारत के वाणिज्यिक और सामरिक हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा. इस पूरे प्रकरण के विभिन्न पहलुओं पर आधारित **इन-दिनों** की प्रस्तुति...

रियायत खत्म होते ही
तेल आयात की बढ़ेंगी मुश्किलें!

ईरान से तेल खरीद की छूट समाप्त

अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने बीते 22 अप्रैल को घोषणा की है कि भारत समेत जिन आठ देशों (चीन, जापान, तुर्की, इटली, ग्रीस, दक्षिण कोरिया और ताईवान) को ईरान से तेल खरीद के लिए 180 दिन की रियायत मिली थी, अमेरिका उसे और आगे नहीं बढ़ायेगा. इटली, ग्रीस और ताईवान पहले ही ईरान से तेल आयात पर रोक लगा चुके हैं. जबकि चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और तुर्की को दी गयी छूट 2 मई, 2019 को समाप्त हो रही है. अगर ये पांचों देश आगे ईरान से तेल खरीदते हैं, तो इन पर अमेरिकी प्रतिबंध लागू होगा. अमेरिका का उद्देश्य ईरान की सरकार के आय के मुख्य स्रोत को समाप्त करना है. दूसरी ओर, ईरान अमेरिकी प्रतिबंध को अवैध मानता है.

अमेरिका-ईरान के बीच क्या है विवाद

पिछले वर्ष ट्रंप ने ईरान और छह पश्चिमी देशों के बीच वर्ष 2015 में हुए ऐतिहासिक परमाणु समझौते से अमेरिका के अलग होने की घोषणा की थी. समझौते के तहत अमेरिका ने ईरान को आर्थिक प्रतिबंधों से छूट प्रदान की थी. बदले में ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने और कार्यक्रम की जांच अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों से कराने के लिए तैयार हुआ था. ट्रंप का कहना था कि ओबामा के शासनकाल में हुआ यह समझौता अमेरिका के लिए घाटे का सौदा है. अब समझौते को रद्द कर ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया है. असल में इसका उद्देश्य ईरान को नये समझौते के लिए विवश करना है. अमेरिका चाहता है कि परमाणु कार्यक्रम के साथ-साथ ईरान बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम की भी अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों द्वारा निगरानी की अनुमति दे.

ईरान पर प्रतिबंध का असर

➲ **अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान की मुद्रा रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गयी है. सालाना महंगाई दर चार गुना तक बढ़ चुकी है और विदेशी निवेशक बाहर जा रहे हैं.**

विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है भारत

- भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है. देश में कच्चे तेल की 80 प्रतिशत और प्राकृतिक गैस की लगभग 40 प्रतिशत जरूरतें आयात के जरिये पूरी होती हैं.
- ईरान से तेल खरीदनेवाले देशों में चीन पहले और भारत दूसरे स्थान पर है. वर्ष 2018-19 में भारत ने ईरान से 2.35 करोड़ टन तेल खरीदा था. पिछले वर्ष भारत ने कुल 22.04 करोड़ टन कच्चा तेल आयात किया था, जिसका 10 प्रतिशत हिस्सा ईरान से आया था.
- इराक और सऊदी अरब के बाद ईरान भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश है. अप्रैल 2017 और जनवरी 2018 (2017-18 वित्त वर्ष के पहले 10 महीने में) की अवधि में ईरान ने भारत को 1.84 करोड़ टन कच्चे तेल की आपूर्ति की थी.
- सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018-19 के पहले 11 महीनों में भारत ने कुल 128.7 बिलियन डॉलर मूल्य का पेट्रोलियम, ऑयल व लुब्रिकेंट (पीओएल) आयात किया था. इस आयात का नौ प्रतिशत हिस्सा ईरान से आया था.

ईरान से कच्चे तेल पर रोक से 2500 करोड़ का नुकसान!

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आईसीआरए की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, अगर ईरान से आयात किये जानेवाले कच्चे तेल पर रोक लगती है, तो इससे भारतीय रिफाइनरियों को वार्षिक परिचालन लाभ (ऑपरेटिंग प्रॉफिट) में 2500 करोड़ रुपये की चपत लग सकती है. ईरान से तेल आयात करने पर भारतीय रिफाइनरियों को 60 दिनों के क्रेडिट अवधि का लाभ मिलता है, जबकि अन्य आपूर्तिकर्ताओं से मात्र 30 दिनों का लाभ मिलता है. इससे अंदेशा है कि ईरान से तेल का आयात बाधित होने पर घरेलू परिशोधन उद्योग को काफी नुकसान होगा.

वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें होंगी प्रभावित

ईरान से कच्चे तेल के आयात को लेकर जिन आठ देशों को छह महीने की छूट दी गयी थी, उसमें भारत भी शामिल था. अब यह अवधि अगामी 2 मई को समाप्त हो रही है. अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर कह दिया है कि किसी देश को अब आगे प्रतिबंध में कोई छूट या सहूलियत नहीं मिलेगी. ऐसे में अगर ईरानी तेल बाजार से बाहर होता है, तो निश्चित ही भारत समेत पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा. वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों पर नियंत्रण मुश्किल होगा.

भारत के पास विकल्प

मई, 2019 के बाद भारतीय तेल रिफाइनरियों को पर्याप्त मात्रा में कच्चे तेल की आपूर्ति होती रहे, इसके लिए भारत सरकार अलग-अलग स्तरों पर प्रयासरत है. तेल मंत्रालय ने एक वक्तव्य जारी कर कहा है कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कच्चे तेल के प्रमुख उत्पादक देशों से अतिरिक्त आपूर्ति के लिए काम किया जा रहा है. हालांकि, भारत अतिरिक्त समयसीमा की उम्मीद लिये अमेरिका के साथ वार्ता जारी रखने की कोशिश में है. वर्तमान में भारत अपनी तेल की कुल जरूरत का 10 प्रतिशत हिस्सा ईरान से पूरा करता है. मौजूदा वित्त वर्ष में भारत ईरान से 2.4 करोड़ टन कच्चे तेल का आयात कर चुका है. ईरान भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है.

भारत-ईरान व्यापारिक संबंध पर सीधा असर

भारत का ईरान के साथ बहुत पुराना संबंध है और ईरान से तेल आयात करनेवाला भारत तीसरा सबसे बड़ा देश है. भारत में तेल की मांग का तकरीबन 12 प्रतिशत हिस्सा ईरान से आता है. इसलिए भारत के लिए ईरान बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन दोनों में एक अटूट संबंध है. यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत डॉलर के मुकाबले रुपये में ही ईरान से तेल खरीदता है और फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत भी नहीं पड़ती. जाहिर है, इससे तेल सस्ता पड़ता है. एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भारत को तेल खरीद पर ईरान 60 दिन का क्रेडिट भी देता है, जो दुनिया का कोई देश नहीं देता. और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि भारत तेल के बदले में ईरान को रुपये की जगह चावल या कोई अन्य चीज दे देता है. साथ ही ईरान से तेल निर्यात करने के टर्म्स भी बहुत सुलझे हुए हैं. ये बातें भारत और ईरान के बीच प्रगाढ़ संबंधों का बेहतरीन सबूत हैं.

संदीप बामजई,
आर्थिक मामलों के जानकार

ईरान पर प्रतिबंध लगता है, तो भी भारत के पास कई विकल्प हैं. लेकिन, ईरान के मुकाबले किसी भी अन्य देश से तेल खरीदना भारत के लिए बहुत महंगा सौदा है.

जब से ईरान पर अमेरिका ने प्रतिबंधों का खेल खेलना शुरू किया है, तब से अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ते-बढ़ते अब 75 डॉलर प्रति बैरल हो गयी है. इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा. भारत तकरीबन 80 प्रतिशत तेल विदेश से खरीदता है. एक तरफ भारत में तेल की मांग लगातार बढ़ रही है, तो वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल का दाम भी बढ़ रहा है. इसका मतलब साफ है कि तेल की धार महंगी होगी ही.

सऊदी अरब, अबूधाबी, कतर आदि देशों से भी भारत के अच्छे संबंध हैं, जहां से हम तेल खरीद सकते हैं. लेकिन, इनके साथ समस्या है कि ये देश भारत से रुपये में पेमेंट नहीं लेते और न ही इतना क्रेडिट ही देते हैं. इसलिए भारतीय तेल कंपनियों- भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल- का ईरान के साथ अच्छे संबंध हैं. ईरान के साथ भारत अब एक रणनीतिक योजना पर काम कर रहा है, जिसके तहत भारत ने ईरान के चाबहार में एक पोर्ट बनाने में निवेश किया है. ठीक उसी तरह से, जैसे पाकिस्तान के ग्वादर में चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना- ओबीओआर है. चाबहार एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जिससे भारत और ईरान के बीच तेल व्यापार को एक नया आयाम मिलेगा.

मध्य-पूर्व में सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देश ईरान के खिलाफ हैं. वहीं अमेरिका तो सऊदी अरब और यूएई के साथ खड़ा है, पर ईरान के खिलाफ है. यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का इन सभी के साथ अच्छे संबंध हैं. इसलिए भारत के लिए मुश्किल है कि वह अमेरिका की सुने या फिर ईरान के साथ अपने प्रगाढ़ संबंधों को बनाये रखे.

ईरान पर प्रतिबंध लगता है, तो भी भारत के पास कई विकल्प हैं. वह सऊदी अरब या अबुधाबी से तेल खरीद सकता है, यहां तक कि वह अमेरिका से भी खरीद सकता है. लेकिन, ईरान के मुकाबले किसी भी अन्य देश से तेल खरीदना भारत के लिए बहुत महंगा सौदा है. तेल की वैश्विक अर्थव्यवस्था में ईरान शीर्ष पांच देशों में है. ईरान प्रतिदिन 3.5 मिलियन बैरल कच्चे तेल उत्पादन करता आ रहा था, लेकिन खींचतान के चलते आज ईरान प्रतिदिन मात्र 2.7 मिलियन बैरल तेल उत्पादित करता है. स्वाभाविक है कि इसका असर ईरानी अर्थव्यवस्था के साथ ही तेल की वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा.

इधर अमेरिका ईरान पर दबाव डालता है, उधर इस्त्राइल भी अमेरिका पर दबाव डालता है. अब अगर ईरान पर प्रतिबंध लगते हैं, तो वैश्विक तेल के दाम पर असर होगा, जिसका सीधा असर भारत पर होगा, चीन पर होगा, ग्रोथ पर होगा, आयात पर होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट पर होगा. यानी एक की वजह से दर्जनों चीजों पर सीधा और ऑटोमेटिक असर पड़ेगा.

वैश्विक ऊर्जा समीकरण बदलेंगे भारत और चीन!

दुनिया का दूसरे और तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक देश चीन और भारत संयुक्त रूप से मिलकर एक 'खरीदार गुट' बनाने की प्रक्रिया में हैं. यह गुट तेल आपूर्तिकर्ता देशों से तेल खरीद के लिए मोलभाव करेगा, साथ ही तेल कीमतों पर सऊदी अरब के नेतृत्व वाले निर्यातक संघ के प्रभाव को भी कम करेगा. इसी के मद्देनजर बीते महीने चीन के राष्ट्रीय ऊर्जा प्रशासन के डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर ली फानरॉन्ग भारत दौरे पर आये थे. परस्पर साामरिक तौर पर प्रतिद्वंद्वी दोनों देशों ने संयुक्त रूप से कच्चे तेल का आयात करने की योजना बनायी है. अगर यह योजना प्रभावी तरीके से लागू होती है, तो निश्चित ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर बदल सकता है. भारत खरीदार गुट को और मजबूत व प्रभावी बनाने के लिए जापान तथा दक्षिण कोरिया को भी साथ शामिल करना चाहता है. जापान और कोरिया क्रमशः दुनिया के चौथे और पांचवें सबसे बड़े तेल आयातक देश हैं.

महंगाई में वृद्धि का अनुमान

चालू खाता घाटे के बढ़ने से रुपये में गिरावट की स्थिति पहले ही देखी जा चुकी है. ऐसे में कच्चे तेल की कीमतों में प्रति बैरल 10 डॉलर की बढ़ोतरी से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का चालू खाता घाटा 0.4 प्रतिशत बढ़ेगा. ऐसी स्थिति में महंगाई का दबाव बढ़ना स्वाभाविक है. अनुमानतः कच्चे तेल की कीमत में प्रति बैरल 10 डॉलर की वृद्धि होने पर भारत की महंगाई में 10 बेसिस प्वॉइंट की बढ़ोतरी होगी.

भारत की आयात पर निर्भरता

(आंकड़े प्रतिशत में)

वर्ष	कच्चे तेल पर	प्राकृतिक गैस पर
2015-16	80.6	40.7
2016-17	81.7	44.5
2017-18	82.9	45.3
2018-19*	83.3	47.0

*(अप्रैल-अक्तूबर/ प्रोविजनल डाटा)
स्रोत : पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय

वित्त वर्ष 2019 में विभिन्न देशों से भारत द्वारा आयात

(बिलियन डॉलर में)

देश	आयात के मूल्य	कल हिस्सेदारी
सऊदी अरब	22.4	17.4
इराक	20.6	16.0
यूएई	12.3	9.6
ईरान	11.6	9.0
नाइजीरिया	9.5	7.4
कतर	8.6	6.7
वेनेजुएला	6.6	5.1
कुवैत	5.8	4.5
अमेरिका	4.7	3.7

11 महीने के आंकड़े, 128.7 बिलियन डॉलर का कुल पीओएल (पेट्रोलियम, ऑयल व लुब्रिकेंट) आयात
स्रोत : सीएमआईई

ईरान से तेल आयात हुआ आधा

- अमेरिकी प्रतिबंधों के लागू होने के बाद बीते वर्ष नवंबर से भारतीय रिफाइनरों ने ईरान से तेल खरीद को लगभग आधा कर दिया है.
- कमी की भरपाई करने के लिए भारतीय रिफाइनर पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) से योजनाबद्ध तरीके से तेल खरीद में वृद्धि कर रहे हैं.

होर्मुज जलडमरूमध्य बंद करने की धमकी

अमेरिका द्वारा भारत समेत बड़े तेल उपभोक्ता देशों की तेल खरीद पर रोक लगाने के बाद ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने की धमकी दी है. होर्मुज जलडमरूमध्य ओमान सल्तनत के दक्षिणी तट और उत्तरी सिरे के बीच का वह संकरा रास्ता है जिसके जरिये दुनिया का एक तिहाई समुद्री तेल हर दिन गुजरता है. इससे पहले भी ईरान इस रास्ते को बंद करने की धमकी दे चुका है, जिस कारण वर्षों तक पश्चिमी देशों के साथ ईरान के रिश्ते उतार-चढ़ाव भरे रहे हैं.

चाबहार बंदरगाह है अहम

ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में हिंद महासागर स्थित चाबहार बंदरगाह भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. इस बंदरगाह को भारत और ईरान मिलकर विकसित कर रहे हैं. चाबहार मध्य एशियाई देशों के साथ भारत, ईरान और अफगानिस्तान के व्यापार का द्वार माना जाता है. इसका सामरिक महत्व भी है. मई 2016 में भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत तीनों देश पारगमन और परिवहन गलियारे की स्थापना के लिए चाबहार बंदरगाह का इस्तेमाल कर सकेंगे.

ऊंचे स्तर पर तेल कीमतें

ब्रेंट क्रूड बेंचमार्क के आधार पर मापे जानेवाले कच्चे तेल का वैश्विक मूल्य बीते 25 तारीख को रिकॉर्ड 75 डॉलर प्रति बैरल के पार चला गया. आशंका है कि यह कीमत 80 डॉलर प्रति बैरल को पार भी कर सकती है. तेल खरीद की छूट मियाद नहीं बढ़ाये जाने और रूस द्वारा कच्चे तेल के निर्यात में कटौती करने के कारण ही इस वर्ष पहली बार वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें इतने ऊंचे स्तर पर पहुंच गयी हैं.

अमेरिका से होगी एलएनजी, इथेन की खरीद

- दो वर्ष पहले भारत ने पहली बार अमेरिका से कच्चे तेल का आयात किया था. 2 अक्तूबर, 2017 को अमेरिकी कच्चे तेल की पहली खेप पारादीप पहुंची.
- अक्तूबर, 2017 के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की चार इकाईयों ने 11.84 मिलियन बैरल कच्चे तेल का ऑर्डर दिया है, जिसका मौजूदा बाजार मूल्य लगभग 730 मिलियन डॉलर है.
- आठ मिलियन मीट्रिक टन तरल प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी (लिक्विफाइड नेचुरल गैस) और संघनित इथेन (कंडेनसैट इथेन) प्रतिवर्ष अमेरिका से खरीदने का अनुबंध किया है भारतीय कंपनियों ने.
- 30 मार्च, 2018 को अमेरिका से आनेवाली लंबी अवधि की एलएनजी की पहली खेप भारत ने हासिल की.
- फरवरी 2018 तक भारतीय तेल कंपनियों ने ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इराक, कजाकिस्तान, लीबिया, मोजाम्बिक, नाइजीरिया, रूस और यूएई सहित 27 देशों के शेयर प्राप्त किये थे.
- हाल ही में भारतीय संघ, जिसमें ओवीएल, आईओसी और भारत पेट्रोरिसोर्सेस लिमिटेड शामिल हैं, ने यूएई के लोअर जखुम अपतटीय तेल क्षेत्र (ऑफशोर ऑयल फील्ड) में 10 प्रतिशत और आईओसीएल ने ओमान के मखैजना तेल क्षेत्र में 17 प्रतिशत का संग्रहण किया.